# रसूखदारों की चल रहीं दो दर्जन से अधिक फर्शी पत्थर की खदानें

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। जिले के पवई, सलेहा एवं शाहनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत 250 मीटर के क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक फर्शी पत्थर खदानों की मंजूरी शर्तों के साथ दी गई थी। इसके बाद भी खदानों को चलाने में शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। खदानों के संचालन में नियमों का पालन नहीं करने वाले इन संचालकों के कारण आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद भी इन रसूखदार खदान संचालकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है।**

गौरतलब है कि खनिज विभाग को वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में खदानों के संचालन की लीज देने का अधिकार नहीं है। इससे इस तरह के आवेदन फाइलें संबंधी कमिश्नर के पास भेजी जाती हैं। जिले के अकेले सलेहा क्षेत्र में कमिश्नर कार्यालय की ओर से वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में दो दर्जन से अधिक खदानों को चलाने की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है लेकिन हमेशा से यही होता आ रहा है कि नियम एवं शर्तें केवल लीज लेने के समय तक कागज में दर्ज रहती हैं और फिर मनमाने तरीके से अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जाना आम बात रहती है।

इन क्षेत्रों में शर्तों के मुताबिक नहीं खदानें:-सलेहा, जैतूपुरा, बछौन, कुटमी, लिलवार, जूडा, सगरा, बडौरा, बिल्हा, घुटेही, हरदुआ, कुटनी, मोहडिया, ककरी क्षेत्र आदि में करीब दो दर्जन से भी अधिक खदानें स्वीकृत हैं। इनके संचालकों में कोई भी खदान मालिक शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। संयुक्त रूप से सीमांकन नहीं होने के कारण खदान संचालकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वन, राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की जरूरत है।

### शर्तों का कर रहे सभी ठेकेदार खुलेआम उल्लंघन

जिन शर्तों के साथ वन सीमा से सटे क्षेत्र में फर्शी पत्थर खदानों की अनुमति की गई थी, उनमें से कोई भी खदान संचालक शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। मैदानी वनकर्मियों की ओर से विभाग को भेजी गई शिकायतों में बताया गया कि अधिकांश लोग स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में या फिर कहीं और खुदाई कर रहे हैं। चोरी-छिपे वे वन क्षेत्र में भी खुदाई कर जाते हैं। नियमों का पालन नहीं करते। इस बारे में वन विभाग के पास आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। वन विभाग इन शिकायतों को खनिज और प्रशासन के पास भेजने की बात कहता है।

# सायबर सेल की तत्परता से 70 हजार रूपये की राशि की गई वसूल

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। दिनांक 22 सितंबर को आवेदक तुषार मलिक निवासी गुनौर के साथ एक साइबर ठगी की घटना घटित हुई थी, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर ओटीपी एवं कार्ड संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली गई।**

इस छलपूर्वक कार्यवाही के माध्यम से ठग ने आवेदक के खाते से लगभग 70,000/- (सत्तर हजार रुपए) की राशि आहरण कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आवेदक तत्काल थाना गुनौर पहुँचा, जहाँ पर तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक भदौरिया द्वारा तत्परता दिखाते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी सायबर सेल पन्ना को प्रेषित की गई।

सायबर सेल पन्ना की टीम द्वारा घटना की गहराई से जाँच करते हुए संबंधित क्रेडिट कार्ड नंबर एवं ट्रांजेक्शन आईडी का विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात सायबर टीम ने संबंधित वॉलेट एवं मर्चेंट कंपनियों से संपर्क स्थापित कर राशि को ब्लॉक कराते हुए सफलतापूर्वक पूरी राशि रिकवर करा ली। इस प्रकार आवेदक तुषार मलिक को उनकी सम्पूर्ण 70,000/- की राशि वापस कराई गई।

# सामान्य से अधिक हुई वर्षा फिर भी खाली पड़े तालाब

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। पन्ना जिले में इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अब तक जिले में 1136.3 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके बाद भी नगर का वाला लोकपाल सागर तालाब आधा भी नहीं भर पाया।**

धरम सागर भी करीब डेढ़ फीट तक खाली है। औसत से ज्यादा बारिश के होने बावजूद भी नगर एक लोकपाल सागर तालाब पूरी तरह से नही भर पाया है। यह आधे से भी अधिक खाली पड़ा हुआ है।

नगर की जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत है पन्ना के प्राचीन तालाब:- नगर की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से प्राचीन तालाबों पर टिकी हुई है। यहां तीनों तालाब सालभर पन्ना वासियों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा बने हुए हैं। नगर से महज 18 किमी दूर जीवनदायिनी केन नदी बहती है, लेकिन अब तक वहां से पानी लाने के लिए शासन-प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की। लोगों का मानना है कि यदि केन नदी से पन्ना नगर तक जलापूर्ति की व्यवस्था हो जाए तो न सिर्फ जल संकट स्थायी रूप से खत्म होगा। तालाबों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। हर साल बारिश पर निर्भर रहने के बजाय प्रशासन को स्थाई कदम उठाना चाहिए। जिससे समस्या कम नहीं हो।

# कलेक्टर ने की विकासखण्डवार खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न हितग्राहियों को प्रत्येक माह समय पर राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न का उठाव कर पारदर्शिता के साथ राशन का वितरण कराएं। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर सभी पात्र लोगों को अनिवार्य रूप से पांच दिवस में राशन वितरित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेवारी तय कर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।**

जिला कलेक्टर ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई खाद्यान्न उठाव व वितरण की विकासखण्डवार समीक्षा बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए। इस मौके पर खरीफविपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान पंजीयन एवं आगामी उपार्जन कार्य की भी समीक्षा की गई। बैठक मे अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी नरेन्द्र सिंह धुर्वे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी व समिति प्रबंधक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती परमार ने दुकानवार खाद्यान्न उठाव की जानकारी लेकर दो दिवस में परिवहन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिले के नगरीय

क्षेत्र में संचालित 32 एवं ग्रामीण क्षेत्रों की 400 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गत माह के खाद्यान्न वितरण के बारे में पूछा तथा नियमित रूप से समय पर सभी दुकानों को खोलने के निर्देश भी दिए। मुनादी एवं अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर आम जनता को राशन वितरण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारी को खाद्यान्न उठाव व वितरण की अद्यतन स्थिति से प्रतिदिन अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पोर्टल पर भी अविलंब वांछित जानकारी की फीडिंग के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक स्तर पर समन्वय की बात भी कही। कलेक्टर ने अमानगंज और शाहनगर क्षेत्र में कुछ अन्नदूत परिवहनकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरतने पर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर वैकल्पिक व्यवस्था और एमडीएम खाद्यान्न उठाव के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में विक्रेताओं को देय कमीशन एवं वेतन का प्रतिमाह भुगतान करने तथा नवीन पात्रता पर्ची एवं नवीन सदस्य के नाम खाद्यान्न पर्ची में जोड़ने के संबंध में अभियान मोड में वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय भी लिया गया। इस अवसर पर आगामी दिसम्बर माह में धान उपार्जन कार्य शुरू होने के संभावना के दृष्टिगत प्रस्तावित केन्द्रों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तथा प्राथमिकता के साथ सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

## लाडली बहनों को मिली अक्टूबर माह की सहायता राशि

पन्ना 12 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को वर्तमान अक्टूबर माह की मासिक सहायता राशि का सिंगल क्लिक के जरिए बैंक खाते में अंतरण किया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ऊषा परमार सहित, अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश सिंह एवं योजना की हितग्राही महिलाएं भी उपस्थित रहीं।

# पन्ना के जंगलों में मिलती हैं दुर्लभ जड़ी बूटियां

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। पन्ना के जंगलों में दहिमन और मलकांगनी जैसी अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती है। इनके संग्रहण उपयोग, संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन और आयुष महकमे के पास कोई प्लान नहीं है। इससे इन दुर्लभ जड़ी-बूटियों का हम उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं।**

अवैज्ञानिक तरीके से विदोहन के चलते कुछ जड़ी-बूटियों के विलुप्त होने का भी खतरा है। जरूरत इनको सहेजने, संग्रहण और प्रोसेसिंग की बेहतर कार्ययोजना बनाने की है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली औषधियों और जड़ी बूटियों के मामले में जिले के कल्दा और पवई के जंगल बुंदेलखंड में सबसे समृद्ध है।

जानकारों के अनुसार वर्ष 2014 के पूर्व तक कल्दा और पवई के जंगल दुर्लभ जडी बूटी मलकांगनी का बडा बाजार होते थे। दहिमन भी यहां बहुतायत में पाई जाती थी।

**अवैज्ञानिक विदोहन, विलुप्त होने का डर:-** पन्ना के जंगलों में पाई जाने वाली जडी बूटियों का अवैज्ञानिक तरीके से विदोहन किया जा रहा है। इसके कारण कुछ दुर्लभ श्रेणी की औषधि की जंगलों से विलुप्त होने की कगार पर है। इन दुर्लभ जडी बूटियों को सहेजने और वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण के लिए कार्ययोजना की आवश्यकता है। जिसे अमल में लाकर हम इनका लोगों के इलाज मे उपयोग हो सके।

**संग्रहण और प्रोसेसिंग की बने कार्ययोजना:-** जिले के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों के संग्रहण, उपयोग और प्रोसेसिंग की कोई कार्ययोजना नहीं है।

### जंगलों में उपलब्ध औषधीय पौधे

कल्दा पहाड में आंवला, सफेद मुसली, बेल सतावर, नगरमोथा, चरोटा बीज, कालमेघ, गुडमार, कलिहारी, हर्रा, बहेरा, पवई क्षेत्र के जंगलों में आंवला, नगरमोथा, चरोटा बीज, धवई फूल, बेल, सफेद मुसली सहित अन्य प्रजातियों के पेड पौधे मौजूद हैं। इनके वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण के लिए लोग प्रशिक्षित नहीं है।

## सहायक उप निरीक्षक आनंद मोहन मिश्रा पवई में पदस्थ

पवई 12 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू द्वारा जिले में कानून व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मचारियों के फेरबदल किए गए हैं इसी कड़ी में सहायक उप निरीक्षक आनंद मोहन मिश्रा चौकी प्रभारी चंदोला थाना अजयगढ़ को पवई में पदस्थ किया गया है उल्लेखनीय है कि आनंद मोहन मिश्रा द्वारा चौकी प्रभारी चांदोरा के पद पर सराहनीय कार्य किया गया है और दशहरा पर्व दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में डूब रहे एक युवक की जान बचाई थी जिस कार्य की पूरे जिले में सराहना की जा रही हैं।

# नौंवी एवं 12 वीं की छमाही परीक्षाएं नवंबर में

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। सरकारी स्कूलों में नौवीं से 12 वीं तक की छमाही परीक्षाएं 3 नवंबर से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड व वार्षिक परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। एमपी राज्य ओपन बोर्ड इन कक्षाओं के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रशिक्षित शिक्षकों से तैयार कराए जाएंगे। इस बार मप्र बोर्ड 10 वीं व 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं सात फरवरी से आयोजित की जाएगी।**

हर साल की अपेक्षा इस साल करीब 15 दिन पहले बोर्ड परीक्षा होगी। इसे देखते हुए इस बार छमाही व प्री बोर्ड परीक्षाएं भी एक माह पहले होंगी। नोवीं से 12 वीं की छमाही परीक्षाएं नवम्बर से होगी। पिछले साल तक ये परीक्षाएं दिसंबर में होती थी। इससे छमाही परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करने का भरपूर समय मिल जाएगा। इस बार बोर्ड परीक्षाएं इसलिए जल्दी आयोजित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की दो परीक्षाएं कराया जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक मुख्य परीक्षा फरवरी में कराने के लिए समय सारिणी जारी करा दी है। दूसरी परीक्षा जून मे आयोजित किए जाने की संभावना है। इस कारण स्कूल शिक्षा विभाग को छमाही परीक्षा का कार्यक्रम परिवर्तित करना पडा है। विभागीय अधिकारयों का कहना है कि दिसंबर की बजाए अब नवंबर से छमाही परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस कारण विभाग ने स्कूलों के करीब 50 से 60 फीसदी पाठ्यक्रम अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

### राज्य स्तर पर तैयार होंगे प्रश्नपत्र

नौवीं से 12 वीं की छमाही परीक्षा बोर्ड व वार्षिक की तर्ज पर होगी राज्य स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। 9 वीं 11 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में छमाही परीक्षा के अंक जोडे जाते हैं। परीक्षा बाद हर विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जो विद्यार्थी का रिपोर्ट कम अंक लेकर आएंगे उनकी अलग से तैयारी कराई जाएगी। उनकी अतिरिक्त कक्षाएं लगेगी क्योंकि वार्षिक व बोर्ड परीक्षाओं में हर स्कूल को 100 फीसदी रिजल्ट का लक्ष्य दिया गया है।

# बिजली की झूलते तारों से हो रही दुर्घटनाएं

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबरझ्र। एक तरफ केन्द्र व राज्य द्वारा विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में लाइट पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। वही दूसरी तरफपहले से लगे विद्युत पोल एवं तारों का मेन्टीनेंस यथासंभव समय पर नहीं किया जा रहा है। लिहाजा कई स्थानों पर तारों का मकड़जाल है तो कई स्थान ऐसे है जहां तार ढीले हो चुके है।**

जिसके कारण आये दिन हादसे हो रहे हैं हाल ही मे विगत सप्ताह पन्ना टाईगर रिजर्व मे एनएमडीसी हिनौता की बाउंड्री के ऊपर झूल रहे ढ़ीले तारों की चपेट मे आने से वन्य प्राणी तेंदुए की मौंत हो गई थी। इस प्रकार के कई हादसे हो गये हैं लेकिन विभाग इससे अभी भी सबक नहीं ले पा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह के केबलीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर अभी भी पुराने तार में विद्युत प्रवाहित की जा रही है। खुले तार होने और उनका मेंटीनेंस न किये जाने की वजह से वह झूलकर नीचे की ओर आते जा रहे है। स्थिति यह है कि इसे गुजरने वाला ग्रामीण हाथों से छू भी सकता है। जिसके कारण ऐसे लोग जहां आसानी से कटिया लगाकर बिजली चोरी करता है। वहीं अनजान लोगों और मवेशियों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। जिस कारण से गुजरने वाले व्यक्ति और मवेशियों को यह नहीं मालूम ही नहीं पड़ता है कि यहां पर तार झूल रहा है और कटिया फंसाई गई है। जिससे ऐसे लोग अनजाने में विद्युत प्रवाह में जाकर फंस जाते है। जिसकी वजह से ऐसे लोग हादसे का शिकार बन जाते है। आये दिन ऐसी घटनाएं होती रही है। यहां उल्लेखनीय है कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जहां 24 घंटे लाइट देने का वायदा एवं प्रयास किया जा रहा है वहीं यह योजना भी प्लाप होती नजर आ रही है। इन दिनों ग्रामीण अंचलों में लाइट आती जाती रहती है। यदि ट्रांसफार्मर जल जाए तो महीनों लाइन मैनों का चक्कर काटना पड़ता है। तारों के झूलने की वजह से जहां लोगों को हर समय खतरा बना रहता है वहीं मवेशी इसकी जद में आ जाते है।

## सलेहा में चोर चुस्त, पुलिस सुस्त

पन्ना 12 अक्टूबर। सलेहा थाना क्षेत्र के पटना तमोली निवासी शालिनी बिरहा 27 ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि में चोर उनके घर का ताला तोड़कर भीतर रखे सोने चांदी के जेवरात, घरेलू बर्तन और नकदी चोरी कर ले गए। कुल सामान की कीमत लगभग 80,000 रूपये बताई गई है। फरियादी कर रिपोर्ट पद थाना सलेहा में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों की तलाश में छानबीन जारी है।

# कमीशन के चक्कर में धूल खा रही रिसाईकिलिंग मशीन, गड्ढे में दफनाया जा रहा कचरा

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। आज कल नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अमले का ध्यान त्वरित फायदे के ऊपर ज्यादा रहता है इसलिए ऐसे कार्य प्राथमिकता से पहले कराये जाते हैं जिसमें उन्हें निजी फायदा होता हो।**

ऐसा ही एक मामला नगर परिषद पवई में देखने को मिला है जिसमें कचरा निपटान के लिए कमीशन के चक्कर मे रिसाईकिलिंग मशीन तो खरीद ली गई है जिसके लिए पूर्व की व्यवस्थाएं करना तो दूर बिजली कनेक्शन तक नहीं लिया गया। जिससे उक्त मशीन शोपीस बनी धूल खा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में स्वच्छता को लेकर जागरूकता और तकनीकी सुधारों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पवई नगर परिषद की कार्यप्रणाली इस उद्देश्य को ठेंगा दिखा रही है। नगर परिषद कचरे के वैज्ञानिक निपटान की बजाय ट्रेंचिंग ग्राउंड में गड्ढे खोदकर कचरे को दफनाने की गैरजिमेदाराना प्रक्रिया अपना रही है, जिससे पर्यावरण, मिट्टी और भूजल सभी पर खतरा मंडरा रहा है। रात के अंधेरे में गड्ढे खोदकर कचरे को जमीन में दबाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार की शाम अंधेरे में नगर परिषद के कर्मियों ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में गड्ढे खोदकर कचरा दबाया।

**बिगड़ सकता है नगर का पारिस्थितिक संतुलन:-** गड्ढों में दबाए जा रहे प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ और अन्य हानिकारक सामग्री मिट्टी की उर्वरता घटा सकते हैं और लंबे समय में भूजल प्रदूषण का गंभीर कारण बन सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो यदि यह प्रक्रिया जारी रही, तो आने वाले वर्षों में जमीन खेती लायक नहीं बचेगी और नगर का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।

**प्रशासन की चुप्पी पर सवाल:-** नगर परिषद की इस कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब रीसाइकिल मशीन मौजूद है, तो आखिर उसे चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन और संचालन व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस संबंध में प्रभारी सीएमओ विनीत नगायच के मोबाइल पर मैसेज भेज सवाल भी किया गया पर सीएमओ मैसेज पढ़ने के बाद भी जवाब नहीं दे पाए।

### री-साइकिल मशीन बंद, बिजली कनेक्शन का इंतजार

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नगर परिषद में लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई कचरा री-साइकिल मशीन वर्षों से ट्रेंचिंग ग्राउंड में धूल फांक रही है। अब तक मशीन को चालू करने के लिए बिजली का कनेक्शन तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटान की पूरी योजना ठप पड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मशीन की उपलब्धता के बावजूद आवश्यक आधारभूत सुविधाएं न होना, स्थानीय नगर प्रशासन की लापरवाही और कुप्रबंधन को उजागर करता है।

# पवई में शिक्षा सुधार के लिए हुई मासिक समीक्षा बैठक

नवभारत न्यूज

**पवई 12 अक्टूबर। जनपद शिक्षा केंद्र पवई में शनिवार को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी संतोष गौतम की अध्यक्षता एवं बीआरसी राजेश पटेल के संयोजन में विकासखंड स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक का सफल आयोजन किया गया। बैठक में सभी 13 जनशिक्षा केंद्रों के जनशिक्षक एवं सह-समन्वयक साक्षरता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ।**

बैठक में चाइल्ड ट्रेकिंग एवं मेन स्ट्रीमिंग के संबंध में दिवाकर मणि पटेल ने विस्तृत जानकारी प्रदान की, वहीं एमआईएस प्रभारी जितेन्द्र सिंह पैड़ो ने यू-डाइस प्लस पर बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन व मेन स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया समझाई। एमडीएम प्रभारी जय सिंह ने मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और ऐप संचालन पर चर्चा की। बीएसी श्रीकांत पटेल ने आवधिक आंकलन

ट्रैकर एवं पुस्तकों के प्रभावी वितरण पर चर्चा की। ब्लॉक साक्षरता सह-समन्वयक रमेश प्रजापति ने आदर्श सामाजिक चेतना केंद्र के संचालन पर मार्गदर्शन दिया। एमआरसी महेश्वरी पटेल ने दिव्यांग बच्चों की योजनाओं, चिन्हांकन, विशेष शिक्षण सहायता की जानकारी बैठक में साझा की विकसित भारत बिल्डाथोन 2025= ब्लॉक प्रभारी अमित रेले ने शिक्षक व छात्र पंजीकरण तथा नवाचारी आइडियाज पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया स्पष्ट की। ब्लॉक ऑपरेटर बड्डू यादव ने गणवेश, साइकिल, वितरण एवं शाला अधोसंरचना के संबंध में चर्चा की व जानकारी संकलित की। बीआरसी राजेश पटेल ने बैठक के सभी एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा व विस्तृत समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट साझा की। प्रभारी बीईओ संतोष गौतम ने सभी जनशिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, छात्रों की उपस्थिति में सुधार, और सभी कंपोनेंट्स समय पर पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए बैठक का संचालन विकासखंड अकादमिक समन्वयक रघुवीर तिवारी ने किया। अंत में सभी उपस्थित शिक्षकों और अधिकारियों ने एकमत से शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नए कदम उठाने तथा निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण करने का संकल्प लिया।

# आरटीओ के संरक्षण में ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में चल रही जानलेवा खटारा स्कूली बसें

## आरटीओ कार्यालय के कैमरे हैं गवाह कि हफ्ते में दो दिन के लिए आते हैं आरटीओ , आखिर आरटीओ कार्यालय में प्राइवेट दलालों का जमघट किसके संरक्षण में

नवभारत न्यूज

**पन्ना 12 अक्टूबर। स्कूल बसों में सुरक्षा के लिहाज से कई पुख्ता कानून निश्चित किये गये हैं। जिनका पालन कराना भी शासन की ओर से अनिवार्य किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निजी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल वाहन पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी।**

यह सख्ती की फिलहाल अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही स्कूल बसों पर थोड़ी बहुत में चल रही स्कूल बसों पर थोड़ी बहुत नजर आ रही है वह भी नाममात्र का लेकिन कस्बाई एवं ग्रामीण इलाकों में संचालित निजी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही स्कूल बसों पर कानून का कोई असर देखने में नहीं आ रहा है। मामला चाहे जहां का भी हो पर नौनिहालों की सुरक्षा का आज भी निजी स्कूल संचालक नजर अंदाज कर रहे है। इसके पीछे हफ्ते मे एक दो दिन के लिए आरटीओ का पन्ना आना एवं अपना उल्लू सीधाकर वापस चला

जाना। जिला परिवहन कार्यालय का यह हाल है कि वहां प्राइवेट दलाल वसूली के लिए रखे गये हैं जो अवैध वसूली कर बकायदा पर्ची सिस्टम से चुकारा किये जाने की चर्चाएं व्याप्त हैं।

स्थानीय जिम्मेदारों ने मूंदी आंख:- निजी स्कूल संचालक अपने फायदे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के साथ यातायात कानून को भले ही नजर अंदाज कर रहे हैं लेकिन इस मामले में स्थानीय परिवहन कार्यालय उतनी ही जिम्मेदार है जितना की स्कूल संचालक। दरअसल जिले में तकरीबन सभी कस्बाई क्षेत्रों में निजी स्कूल संचालित हैं। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों मे भी अंग्रेजी माध्यम के मंहगे निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन सभी में बस व आटो रिक्शा से छात्रों को आवागमन कराया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी स्कूल वाहनों की निगरानी क्यों नहीं कर रहे। जब कभी कोइ हादसा होता है तो कुंभकर्णी नींद मे सो रहे आरटीओ महोदय जाग जाते हैं अभी दो दिन पूर्व अमानगंज थाना अंतर्गत एक खटारा बस के पलट जाने से लगभग एक दर्जन बच्चा घायल हो गये थे। तभी वे अपने कुंभीकर्णी नींद से जागते हुए दूसरे दिन एक दो वाहन चेक कर पीआरओ कार्यालय से प्रेस नोट जारी कर अपनी कर्तव्य परायणता की इतिश्री कर लेते हैं। जिला परिवहन कार्यालय मे लगे कैमरे इस बात के गवाह हैं कि आरटीओ सुनील शुक्ला महीन मे 4 - 6 से अधिक कभी नहीं आते हैं। सूत्र बताते हैं कि स्कूल वाहन में कागजातों के अलावा न तो सीसी कैमरे हैं और न ही स्पीड गर्वनर लगाया गया है। जीपीएस सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। बताया गया कि बस में क्षमता से अधिक छात्र से भरे जा रहे हैं और पुलिस देखती रहती है।

### अभिभावकों की भूमिका

बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों द्वारा निजी का चयन किया जाना समझ में आता है लेकिन स्कूलों द्वारा की जा रही लापरवाही को अभिभावक नजर अंदाज कर देते है यह बात समझ में नहीं आती। छात्र को प्रवेश दिलाने के पहले अभिभावक की यह जवाबदारी बनती है कि सबसे पहले वह स्कूल की उप व्यवस्थाओं की जानकारी ले जिनसे छात्र की सुरक्षा निश्चित होती है। यही पर अभिभावक गलती कर जाते है और उसी का फायदा निजी स्कूल संचालक उठा रहे है।

### क्या है कानून

विगत एक साल में स्कूल बसों मे हुए हादसों से कई तरह के सुरक्षा इंतजाम शासन द्वारा नियत किये गये हैं। बनाये गये नये सुरक्षा कानून के तहत स्कूल वाहन में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस सिस्टम, अनुभवी बस चालक, महिला अटेंडेंट, फ्रस्ट, एड बाक्स, स्पीड गर्वनर, आरटीओ के सही कागजात व बस में दो गेट सहित अग्निशामक यंत्र रखा जाना निश्चित किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि किसी भी स्कूल बस में इन सुरक्षा उपायों का मिलना असंभव है। इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही प्रतीत होती है।